www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 291 | जौनपुर शुक्रवार, 12 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

अगले कुछ घंटों में पंजाब के चार जिलों में रेड अलर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अगले कुछ घंटों में पंजाब के चार जिलों में रेड अलर्ट, तेज हवाओं संग भारी बारिश की आशंका भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो–तीन घंटों के लिए कई राज्यों के विभिन्न जिलों में नाउकास्ट चेतावनी जारी की है। विभाग ने तेज हवाओं, भारी बारिश, गरज–चमक और आंधी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है। रेड अलर्ट उन जिलों के लिए जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं (लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा) और भारी बारिश (15 मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक) के साथ बिजली और गरज की आशंका है। पंजाब के बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और संगरूर जिलों में लाल चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों के निवासियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि तेज हवाएं पेड़ उखाड़ सकती हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट उन जिलों के लिए जारी किया गया है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, 5 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से मध्यम वर्षा होने तथा आंधी और वज्रपात की संभावना है। इस चेतावनी के तहत पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी, सीवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण को अलर्ट पर रखा गया है।

पीएम मोदी ने जनता को गुमराह करके 12 साल पूरे किए – प्रियंका चतुर्वेदी

मुंबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने केवल देश की जनता को गुमराह करके अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पहले दो कार्यकाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाई और वर्तमान में वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के समर्थन से तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं।वहीं, कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में उन्होंने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चतुर्वेदी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई वजहों से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय राजनीतिक कारणों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी सवाल उठाया ।

किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र में अपनी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'किसान समृद्धि' का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पीएम–किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल किसानों की आय की सुरक्षा के साथ–साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही हैं। इसके साथ ही, पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान भाई–बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधारस्तंभ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारे किसान भाई–बहन देश की अन्न सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के आधारस्तंभ हैं। उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम–किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ–साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही हैं। पीएम–कुसुम योजना से जहां खेती के लिए उन्हें सौर ऊर्जा सुलभ हुई है, वहीं इससे खेती पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है।" उन्होंने पोस्ट में लिखा, "खेती सहित अन्य जरूरतों के लिए कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के बहुत काम आ

रहा है। उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 'बीज से बाजार तक' की हमारी पहल भी बहुत कारगर साबित हो रही है।" पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए उन्हें कृषि से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हमारा निरंतर जोर रहा है। उन्होंने कहा, "ड्रोन, सॉयल हेल्थ कार्ड और प्राकृतिक खाद से जुड़े अभियानों से भी किसानों को फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है।" एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने 'संस्कृत सुभाषितम्' शेयर करते हुए लिखा, "कृषि केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। हमारे किसान भाई–बहनों का पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो अन्न बनकर देशवासियों के जीवन को संबल देता है। ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति।कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद।"'संस्कृत सुभाषितम्' में कहा गया है, "खेती और फसल ही मनुष्य के जीवन का आधार हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वही कृषि कार्य को सही ढंग से करता है और उसी के माध्यम से समाज का भरण–पोषण होता है।" गौरतलब है कि पिछले एक दशक में भारतीय कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार ने कई पहलों को शुरू किया है, उनका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने और उनकी बेहतर आय रहा है। आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) के तहत 4 करोड़ से अधिक किसान को बीमा का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के तहत अब तक देशभर में किसानों के खातों में 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। 2014–2025 के बीच जलवायु के अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में जारी की गईं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 84,200 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए, जिससे 1.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके अलावा, शुरुआत से अब तक परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत लगभग 19 लाख हेक्टेयर जमीन शामिल की गई। 11 करोड़ किसानों के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी और 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत 109 लाख हेक्टेयर खेती को कवर किया जा चुका है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत लगभग 25 लाख किसान जुड़े। पीएम धन–धान्य कृषि योजना के तहत 24,000 करोड़ बांटे जा चुके हैं। वहीं, देश भर में लगभग 26 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए।

यूपी में मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे धर्मांतरण रोकथाम सेल, राज्यपाल ने दिया निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धार्मिक परिवर्तन रोकथाम सेल (धर्मांतरण रोकथाम सेल) बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक रेजिडेंट डॉक्टर से जुड़े धर्मांतरण मामले और संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक कर्मचारी की बेटी के लापता होने की घटना के बाद उठाया गया है। आदेश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल संस्थानों को तुरंत ऐसे सेल बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों के अनुसार, इन धर्मांतरण रोकथाम सेल का काम छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों, फैकल्टी और अन्य कर्मचारियों को संबंधित कानूनों और संस्थागत जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके अलावा इन सेल को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी शिकायत को उचित तरीके से जांच के लिए आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्थानों को जागरूकता अभियान और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के लिए भी कहा गया है, ताकि छात्र और कर्मचारी कानून, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रख सकें। सभी संबद्ध मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को जल्द से जल्द ये सेल बनाने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इन सेल में आने वाली किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के लिए व्यवस्था बनाने को भी कहा गया है। केजीएमयू धर्मांतरण मामला एक पूर्व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर लगे आरोपों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है।

मोदी सरकार के 12 वर्षों में संसद ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले – किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस दौरान कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना एक अलग बात है, लेकिन संसद के जरिए जो कदम उठाए गए, उन्हें जानना भी जरूरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 12 वर्षों में संसद ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। आजादी के बाद पुरानी संसद जर्जर हो गई थी। कई लोकसभा अध्यक्षों की ओर से नए संसद भवन के निर्माण का आग्रह किया गया था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे खूबसूरत संसद भवनों में से एक का निर्माण

कराया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। नए संसद भवन में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान पर एक काला दाग था, जो जम्मू–कश्मीर को देश से अलग करता था। इसे हटाया गया। ऐतिहासिक जीएसटी विधेयक पारित हुआ और "एक देश, एक टैक्स" की व्यवस्था लागू की गई। कोरोना काल में भी संसद की कार्यवाही जारी रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1,725 पुराने कानून, जिनकी अब जरूरत नहीं थी, उन्हें समाप्त किया गया। पिछड़े वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उनसे जुड़े कानून बनाए गए। आरक्षण और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर भी कानून बनाए गए। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 2017 में महिलाओं की मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) अवधि बढ़ाई गई। चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) में सुधार किए गए। आधार अधिनियम लागू किया गया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान करने वाले कई कानून थे, जिनमें कुछ अंग्रेजों के समय के थे और कुछ आजादी के बाद बनाए गए थे। ऐसे कानूनों को खत्म किया गया। जन विश्वास विधेयक भी पारित किया गया। उन्होंने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए।

राजस्थान को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,228 करोड़ रुपए, अश्विनी वैष्णव ने गिनाई उपलब्धियां

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में रेलवे विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश मिला है, जिससे राज्य में रेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले राजस्थान के लिए रेलवे बजट लगभग 600 करोड़ रुपए हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें लगातार वृद्धि की गई और

अब राज्य को रेलवे विकास के लिए 10,228 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बढ़े हुए निवेश का सीधा लाभ यात्रियों और रेलवे ढांचे को मिला है तथा राज्य में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और नई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान में करीब 450 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से 200 से अधिक स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने, प्लेटफॉर्म का विस्तार करने, यात्रियों के लिए पूर्ण शेड उपलब्ध कराने और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के लगभग 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान को कई नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सहित विभिन्न शहरों से नई अमृत भारत और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जयपुर सांसद की मांग पर शुरू की गई ।

शिवराज सिंह चौहान का किसानों को बड़ा तोहफा, 14 जून को विदिशा में मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 14 जून को विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में देश के एक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश के माध्यम से किसानों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 14 जून विदिशा संसदीय क्षेत्र के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को सुबह 10 बजे बेरखेड़ी जट्टू में किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के शिलान्यास के साथ–साथ विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए तैयार किए गए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप को लागू करने की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा किसानों के हित में 'खेत बचाओ अभियान' भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों को नकली खाद और बीज की पहचान, उनसे

बचाव के उपाय, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग, नई फसल बुआई तकनीक, जैविक खेती, फसल प्रबंधन तथा मौसम आधारित कृषि सलाह जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही आधुनिक कृषि मशीनों का प्रदर्शन, विभिन्न स्टॉल और लाइव डेमो भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसान नई तकनीकों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कृषि विज्ञान केंद्र देश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम विजय, तमिलनाडु की अहम मांगों पर जोर देने की संभावना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजनीतिक सहयोगियों और संबंधित पक्षों की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु के हितों को सक्रिय रूप से रखने की मांग के बीच मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के कल्चरल सेंटर में होने वाली इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस दौरान विकास की प्राथमिकता, केंद्र–राज्य सहयोग और लंबी अवधि की नीतिगत पहलों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक जानकारों और गठबंधन सहयोगियों ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया है कि वे इस मंच का इस्तेमाल तमिलनाडु के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखने और केंद्र सरकार के सामने राज्य की लंबित मांगों पर जोर देने के लिए करें। मुख्यमंत्री विजय बुधवार को एक प्राइवेट विमान से नई दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में यह उनका दूसरा दौरा है। वे दोपहर में तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउस पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, इनमें राष्ट्रीय राजधानी में तैनात तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी शामिल थे। नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ कई अहम बैठकें कीं। बुधवार शाम उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और राज्य व देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के आवास पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इन मुलाकातों को संवैधानिक अधिकारियों और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने की विजय की कोशिशों के तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी है। एक और अहम मुलाकात में विजय ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में सीपीआई के महासचिव डी राजा से मुलाकात की और अपनी सरकार को वामपंथी दलों से मिले समर्थन के लिए उनका आभार जताया।

सीएम योगी और धामी ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, किसानों के सशक्तिकरण की सराहना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन को सराहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश के अन्नदाता किसान के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के नए अध्याय जुड़े हैं। वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के अन्नदाता किसान

के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के नए अध्याय जुड़े हैं। 'बीज से बाजार' तक किसान को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने कृषि को नई शक्ति और किसानों को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।" उन्होंने आगे लिखा, "पीएम–किसान सम्मान निधि ने आर्थिक संबल दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सुरक्षा का भरोसा जगाया, पीएम–कुसुम ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया और ई–नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने किसानों को नए अवसरों और बाजारों से जोड़ा है। अन्नदाता बंधुओं के उत्कर्ष को समर्पित ये गौरवशाली 12 वर्ष 'किसान समृद्धि से राष्ट्र समृद्धि' की ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी हैं।" उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। पीएम–किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सिंचाई और कृषि में तकनीक के बढ़ते उपयोग ने किसानों को सशक्त बनाने का कार्य किया है। अन्नदाता की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लिए गए निर्णयों ने करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।" उन्होंने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संपादकीय

फुलाया गया गुब्बारा फूट चुका

फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है।

जी ग्रुप का फिर से खेल प्रसारण के क्षेत्र में उतरना अच्छी खबर है। रिलायंस ग्रुप के डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लेने और सोनी लिव के भारतीय बाजार में हाथ खींच लेने के बाद जियो–हॉटस्टार की लगभग मोनोपॉली बन गई थी। अब जी ग्रुप ने 11 जून से शुरू हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का टीवी एवं डिजिटल प्रसारण अधिकार खरीद कर फिर से प्रतिस्पर्धा की संभावना जगाई है। बहरहाल, इस क्रम में भारतीय खेल प्रसारण बाजार के सिकुड़ने के संकेत भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार रिलायंस ग्रुप के वायकॉम–18 एवं जियो सिनेमा ने तकरीबन छह करोड़ डॉलर में खरीदे थे। अब चार साल जी ने 2026 और 2030 के वर्ल्ड कप समेत फीफा के नौ टूर्नामेंट्स के प्रसारण का अधिकार सिर्फ साढ़े तीन करोड़ डॉलर में खरीद लिए हैं। बताया जाता है कि 2022 में वर्ल्ड कप प्रसारण के दौरान सिर्फ करीब 300 करोड़ रुपये के विज्ञापन ही जुटाए जा सके। इस कारण इस बार इस टूर्नामेंट का बाजार भाव गिर गया। फीफा ने आरंभिक कीमत सिर्फ 2026 के टूर्नामेंट के लिए 10 करोड़ डॉलर रखी थी। जियो हॉटस्टार ढाई करोड़ डॉलर से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुआ। सोनी भी शुरुआती बातचीत के बाद मैदान से हट गया। तो टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है। कुछ समय पहले ये गौरतलब खबर आई थी कि जियो हॉटस्टार आईसीसी के साथ अपने क्रिकेट प्रसारण समझौतों पर फिर से सौदेबाजी करना चाहता है। इसका कारण है कि मीडिया अधिकार पाने की लागत बहुत अधिक (138 करोड़ रुपये प्रति मैच) पड़ी है, जबकि विज्ञापन राजस्व उतना नहीं है। आम समझ है कि अगले साल जब फिर से मीडिया अधिकार बिकेंगे, तो आईसीसी को पहले से कम भाव पर ये बिक्री करनी होगी। तो कुल मिला कर सिर्फ आईपीएल हॉट प्रोपर्टी बना हुआ है, हालांकि इस वर्ष उसकी टीवी दर्शक संख्या पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

वेनेजुएला के बाद क्यूबा की बारी है

यह आज की बात नहीं है, बल्कि बीती कई दहाइयों से अमेरिका के लिये बुकनी सा कष्टप्रद यह सिलसिला जारी है। दरअसल यह तकलीफदेह क्रम सन 1959 में फिदेल कास्त्रो के कू–दे–ता के जरिये सत्ता में आने के ऐन दिन से शुरू हो गया था। फिदेल को अपदस्थ करने अथवा मारने की सीआईए की सारी कोशिशें विफल रहीं। अमेरिका उनकी मुश्कें नहीं कस सका। उलटे फिदेल वैश्विक नेता के तौर पर उभरते गये और उन्होंने दुनिया भर के मुक्तिकामी जनों को आकर्षित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और क्यूबा के संबंधों को नयी ऊंचाई और सान्द्रता मिली। शीतयुद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा को मुसीबतों से दो–चार होना पड़ा। रही सही कसर अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों ने पूरी कर दी। जारी वर्ष के प्रारंभ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के निर्लज्ज अपहरण से अनेक छोटे और निर्बल राष्ट्र सकते में आ गये। यूं तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अभीष्ट की पूर्ति के लिये ही अमेरिका ने इस्रायल के सहयोग से 28 फरवरी को ईरान पर धावा बोला था और उसे अली खामेनेई समेत अनेक बड़े ईरानी नेताओं को मारने में कामयाबी भी मिली, अलबत्ता उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। अब यह सवाल सारी दुनिया में खतरे की घंटी की मानिंद घनघना रहा है कि क्या वेनेजुएला और ईरान के बाद अब बारी क्यूबा की है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशना कठिन इसलिये नहीं है क्योंकि जिद्दी और अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप अपनी खब्त में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के 14 मई को हवाना की यात्रा और खुलेआम अंतिमेत्थम ने अमेरिका–क्यूबा के कसैले संबंधों मंह इजाफा कर एक करोड़ से कुछ अधिक क्यूबावासियों की रगों में सिहरन पैदा कर दी है। आज नहीं, अर्से से क्यूबा के नसीब में चौन नहीं है और अमेरिकी धौंस, दबंगई और दादागिरी से उसकी मुसीबतों की गठरी भारी होती जा रही है। राजधानी हवाना समेत पूरा क्यूबा अंधेरे में डूबा हुआ है। क्यूबा अभूतपूर्व ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। डीजल और पेट्रोल का भंडार खत्म हो गया है। उसका अपना तेलशोधक संयंत्र फरवरी में आग की भेंट चढ़ गया। तेल की आपूर्ति के लिये उसका मुख्य आलंबन वेनेजुएला था, मगर अब वेनेजुएला अमेरिका का बंधक राष्ट्र है। ऊर्जा संकट का असर, शिक्षा, आहार, चिकित्सा आदि की प्रणालियों पर भी पड़ रहा है। हालत यह है कि राजधानी हवाना में नागरिकों को बाईस–बाईस घंटे ब्लैक आउट का सामना करना पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हैं और लोगों को खाना पकाने के लाले पड़ गये हैं। फलतरू असंतोष गहरा रहा है और मुसीबतजदा लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्यूबा के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो बीते करीब पांच शतियों में उसके संघर्ष की तस्वीर उभरती है। 20 अक्टूबर, सन 1492 को कोलंबस की खोज के बाद यह कैरेबियन–द्वीप समूह स्पेन का उपनिवेश रहा। सन 1868 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की और सन 1895 में आजादी की लड़ाई छेड़ी। सन 1898 में उसे मान्यता तो मिली, लेकिन वह अमेरिका के चंगुल में फँस गया। इसका अंत अंततरू मई, 1902 में हुआ, जब वह गणतंत्र बना। लेकिन यह सौभाग्य भी अधिक दिन टिका नहीं। सन 1933 में कूदेता से बातिस्ता सत्ता में आये और करीब पाव सदी क्यूबा ने उनकी तानाशाही झेली। इससे उसे आखिरकार सन 1959 में फिदेल कास्त्रों ने मुक्ति दिलाई। फिदेल अपनी पॉलिसी से अमेरिका की आँखों की सबसे कर्री किरकिरी बनकर उभरे। अमेरिका ने उन्हें हटाने और निपटाने के लाख जतन किये, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। फिदेल दशक–दर–दशक उसकी छाती पर मूंग दलते रहे। उन्होंने महाबली अमेरिका की नाक तले कम्युनिस्ट रिजीम खड़ी कर दी। सन 1962 का मिसाइल प्रसंग दुनिया भूली नहीं है। यह शीत युद्ध का चरम प्रसंग था। बहरहाल, कास्त्रों ने शिक्षा, चिकित्सा और आवास पर खूब ध्यान दिया। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सस्ते मकानों से उन्होंने क्यूबा का हुलिया बदल दिया। उन्होंने अफ्रीकी देशों व अन्यत्र डॉक्टरों की टोलियां भेजीं और दुनिया में अमेरिकी शिकंजे को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। फलतरू विश्व में मुक्ति कामी का जनता का यह लाड़ला नायक अमेरिका के लिये मोस्ट वांटेड और खलनायक हो गया। उसके कृत्यों में सोवियत संघ उसका सरपरस्त और सहयोगी रहा। आज भी रूस और चीन उसके सहयोगी राष्ट्र हैं। रूस ने इसी साल 30 मार्च को एक लाख टन कच्चा तेल भेजा और चीन ने 80 मिलियन डॉलर की मदद और 60 हजार टन चांवल देने का ऐलान किया। इसी क्रम में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आठ मिलियन और फिर साढ़े पांच मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की। क्यूबा के खिलाफ वाशिंगटन के दबाव के चलते लातिनी अमेरिकी देशों में क्यूबा से कन्नी काटने का दायरा बढ़ता जा रहा है। मेक्सिको की क्लाडिया शीनबाम क्यूबा समर्थक हैं, लेकिन फरवरी में तेल से लदे दो पोत भेजन के पश्चात उन्होंने ट्रंप की नाराजगी के भय से क्यूबा को मदद से हाथ खींच लिये हैं।

सांसद और विधायक भाग रहे, ममता बनर्जी भी टीएमसी छोड़ कर कांग्रेस में जा रही हैं

नीरज

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। कभी बंगाल की निर्विवाद ताकत मानी जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अंदरूनी बगावत, सांसदों और विधायकों के पलायन तथा राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की बैठकों ने इस संकट को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। भले ही कांग्रेस और तृणमूल दोनों सार्वजनिक रूप से किसी विलय की संभावना से इंकार कर रहे हों, लेकिन घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा पुनर्संयोजन शुरू हो चुका है। एक तरह से यह साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ टीएमसी के सांसद, विधायक और पार्षद ही पाला नहीं बदल रहे हैं खुद टीएमसी प्रमुख अपनी पार्टी को खत्म कर कांग्रेस में वापस लौटना चाह रही हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की डेढ़ घंटे लंबी मुलाकात तथा उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इन बैठकों को लोकतंत्र और संविधान बचाने की साझा प्रतिबद्धता बताया, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह महज औपचारिक बातचीत नहीं थी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है और पार्टी के भीतर टूट की स्थिति बनी है, उसके बाद कांग्रेस से नजदीकी बनाना ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर विद्रोह अब खुली चुनौती का रूप ले चुका है। पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग होकर निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ चले गए हैं। इस गुट को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। रितब्रत बनर्जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वही "असली तृणमूल कांग्रेस" हैं और कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के विलय या समझौते के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि उनके साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई सांसद भी उनके संपर्क में हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय या अत्यधिक नजदीकी की अटकलों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर असुरक्षा और बेचैनी को और बढ़ा दिया है। पार्टी के कई विधायक, सांसद और क्षेत्रीय नेता अपनी पूरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस विरोध की जमीन पर बनाकर आगे बढ़े थे। ऐसे में उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि ममता बनर्जी अंततः कांग्रेस के साथ विलय या व्यापक राजनीतिक समझौते की राह पर चलती हैं, तो उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि तृणमूल में भगदड़ और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस में लौटने के पक्ष में नहीं है और वह या तो अलग गुट के साथ रहना चाहता है या फिर नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। यही बेचैनी अब खुले विद्रोह और लगातार इस्तीफों के रूप में सामने आती दिखाई दे रही है। संकट केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। संसद में भी तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलती दिख रही है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उनसे पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात ने यह अटकलें और तेज कर दी हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। लोकसभा में भी तृणमूल के भीतर विद्रोही खेमे की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। काकोली घोष दस्तिदार के नेतृत्व वाला गुट दावा कर रहा है कि उसे बीस से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है। सयोनी घोष, माला राय, युसुफ पठान, शताब्दी राय, शत्रुघ्न सिन्हा और रचना बनर्जी जैसे कई चर्चित नाम विद्रोही खेमे के साथ बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गुट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुका है। इन घटनाओं के बीच कांग्रेस की भूमिका बेहद दिलचस्प हो गई है। बंगाल कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी और अब्दुल मन्नान जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मन्नान ने तो यहां तक कह दिया कि "गंदे पानी को साफ पानी में मिलाने से साफ पानी भी गंदा हो जाता है।" अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर कांग्रेस को बंगाल से खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वही ममता गांधी परिवार के सहारे की तलाश में हैं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मानता है, उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस की छतरी का इस्तेमाल करने वालों के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। यह बयान सीधे तौर पर तृणमूल के उन नेताओं की ओर इशारा माना जा रहा है जिन पर विभिन्न घोटालों के आरोप लगे हैं। हम आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक उदय ही कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह की जमीन पर खड़ा हुआ था। वर्ष 1998 में उन्होंने जोरशोर से कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उस समय ममता ने कांग्रेस नेतृत्व पर बंगाल की राजनीति की अनदेखी करने और वामपंथ के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे बंगाल में कांग्रेस की जड़ें कमजोर कर दीं। वर्ष 2011 में वाम मोर्चे को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए कांग्रेस से पूरी दूरी बना ली थी और लगातार गांधी परिवार तथा कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले करती रहीं। लेकिन अब जब तृणमूल कांग्रेस भीतर से टूट रही है, सांसद और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तब वही ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस की जड़ों की ओर लौटती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में गांधी परिवार के साथ उनकी बैठकों को केवल शिष्टाचार मुलाकात मानने को राजनीतिक विश्लेषक तैयार नहीं हैं। दरअसल, बंगाल की राजनीति अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह अस्तित्व की जंग बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक बिखराव से जूझ रही है और बात सिर्फ संसद या विधानसभा में उसके सदस्यों तक सीमित नहीं रह गयी है। बंगाल में कई निगमों से उसके महापौर या पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं और पंचायतों में भी इसी तरह के इस्तीफों का दौर जारी है। इस सबके बीच भाजपा यह स्पष्ट कर चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए उसके दरवाजे बंद हैं वहीं कांग्रेस इस संकट को अपने पुनर्जीवन के अवसर के रूप में देख रही है।

मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही कांग्रेस का घमंड भी चकनाचूर कर दिया है

नीरज

"मोदी हैं तो मुमकिन है", यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि पिछले बारह वर्षों में भारत की बदलती राजनीतिक और प्रशासनिक तस्वीर का सबसे सशक्त प्रतीक बन चुका है। जिस उपलब्धि को दशकों तक असंभव माना जाता रहा, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभव कर दिखाया है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। लगातार 4399 दिनों तक देश का नेतृत्व करते हुए उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के 4398 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। देखा जाये तो यह उपलब्धि केवल एक रिकॉर्ड टूटने भर की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में आए एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेहरू का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है बल्कि उस राजनीतिक सोच को भी चुनौती दी है जिसमें लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि सत्ता पर केवल एक ही परिवार या एक ही दल का स्वाभाविक अधिकार है। दशकों तक देश की राजनीति गांधी परिवार और कांग्रेस पर केंद्रित रही, लेकिन एक गरीब परिवार से निकले, संघर्षों के बीच पले–बढ़े और कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की ताकत के बल पर देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचकर भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मोदी का यह सफर करोड़ों सामान्य भारतीयों के लिए प्रेरणा का विषय है। यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, और जनता जब ठान ले तो वह किसी भी स्थापित राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए और सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाकर नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट विजन और जनता के भरोसे के दम पर भारतीय राजनीति में असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। देखा जाये तो मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस जनविश्वास की कहानी है जिसने नरेंद्र मोदी को लगातार तीन बार देश की सत्ता सौंपी। आजादी के बाद केवल जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी ने भी वही करिश्मा दोहराया, लेकिन उससे आगे जाकर लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में वह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली और निर्णायक नेता बनकर उभरेंगे। 2019 में उन्होंने पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश हासिल किया और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से नीचे रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की चमक और प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सत्ता संभाली और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दरअसल नरेंद्र मोदी का यह सफर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशासन संभालते हुए सुशासन का एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 4610 दिनों तक राज्य की कमान संभाली। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मिलाकर मोदी अब नौ हजार दिनों से अधिक समय तक किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख रह चुके हैं। मार्च 2026 में उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 8930 दिनों का रिकार्ड भी तोड़ दिया था और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले निर्वाचित प्रमुख बन गए थे। उधर, मोदी के इस ऐतिहासिक मुकाम पर केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयों का सिलसिला मिला। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत और इटली के मजबूत होते रिश्तों का उल्लेख किया। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने इसे दशकों की समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का प्रमाण बताया। अमेरिकी सीनेटर जॉन कोर्निन ने मोदी के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों के विश्वास ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी मोदी की उपलब्धि को भारत की समृद्धि, विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा से जोड़ा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को समर्पण, संघर्ष और जनसेवा का प्रतीक बताया। यह साफ संकेत है कि आज नरेंद्र मोदी केवल भारत के नेता नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। उधर, देश के भीतर भी मोदी की इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल है। भाजपा नेताओं ने आज देशभर के विभिन्न धर्म स्थलों में प्रार्थना कर भारत की खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने की कामना की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की। इसके अलावा, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की गयी और एक अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक सत्तारुढ़ एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। बहरहाल, नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है ।

भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोले

पीयूष गोयल

एक जून से लागू हुआ भारत–ओमान मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस मिशन की एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य नए बाजार खोलने और रोजगार सृजन को गति देने के जरिये भारत के छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के लिए वैश्विक समृद्धि के मार्ग बनाना है। भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200द्300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह तुरंत ही ओमान में 98त्न टैरिफ लाइनों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की सुविधा देता है, जिसमें 99.38 प्रतिशत निर्यात शामिल है। यह सीईपीए से पहले की प्रणाली की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत भारतीय निर्यात ओमान में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते थे। भारत की ऐसी वस्तुएं, जिन पर वर्तमान में ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जिनकी कीमत लगभग 3.64 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर है, अब काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए, यह समझौता परिवर्तनकारी हो सकता है, क्योंकि सीईपीए से लाभान्वित होने वाले कई क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की प्रमुखता है। लोहा और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, वाहन कल–पुर्जे और औद्योगिक उपकरण जैसे कुछ क्षेत्रों में एमएसएमई को बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के युग में, सीईपीए भारतीय निर्यातकों को, जो आर्थिक मंदी और बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, अपने बाजारों को विविध बनाने और परंपरागत बाजारों पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। रोजगार सृजन दृ यह व्यापार समझौता श्रम–गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्रों को लाभ पहुँचाता है, जो भारत के प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं। ओमान को होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, भदोही, मुरादाबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख क्लस्टर में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। भारत भर के कारीगर और बुनकर भी अपने उत्पादों की उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होंगे। भारत भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत चमड़ा और जूता के प्रमुख केंद्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रत्न और आभूषण क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है, जो दिखाता है कि सीईपीए रोजगार वृद्धि को किस प्रकार तेज करेगा। भारत के पास पहले से ही कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण तथा हस्तनिर्मित आभूषण उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। शुल्क बाधाओं के हटने से, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में ओमान को होने वाला निर्यात बढ़ कर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आभूषण निर्माण केन्द्रों में महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है। किसान और मछुआरे – घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि हितों की सुरक्षा के लिए, भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, तिलहन, चाय, कॉफी और शहद जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरीफ छूट नहीं दी है। घी, शहद, मीठे बिस्कुट, अंडे और कुछ मिष्ठान्न उत्पादों में भारत को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे देश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। यह समझौता भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणन की स्वीकृति और मान्यता भी प्रदान करता है, जो भारतीय किसानों को ओमान में, जो एक प्रमुख खाद्य आयातक है, जैविक उत्पाद बेचने के लिए विशाल अवसर देगा। समुद्री उत्पादों में भी विशाल संभावनाएँ हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। 2022 और 2024 के बीच ओमान का समुद्री उत्पादों का आयात लगभग 119 मिलियन डॉलर था। भारत से आयात केवल 7.75 मिलियन डॉलर था, जिससे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात जैसे झींगा और जमे हुए कटलफिश के लिए विशाल अवसर मौजूद हैं। श्रम–गहन समुद्री उत्पाद उद्योग मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत–श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और निर्यात संचालन में अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न कर सकता है। दवा और पारंपरिक चिकित्सा – यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए और टीजीए जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित भारतीय दवाएं 90 दिनों के भीतर ओमान में स्वचालित विपणन प्राधिकार प्राप्त करेंगी कृ जो भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए एक बड़ी सफलता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सीईपीए भारत की पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। यह पारंपरिक चिकित्सा में संयुक्त अनुसंधान की व्यवस्था करता है। सेवाएँ और आवागमन – समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा और आवागमन में निहित है। ओमान ने भारत के लिए विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, कंप्यूटर और आईटी सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरण सेवाएँ शामिल हैं। लेखा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, निर्माण, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुँच से लाभ मिलने की उम्मीद है। महत्त्वपूर्ण रूप से, ओमान ने भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के लिए आवागमन प्रतिबद्धताओं में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है। अंतर–कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों और संविदा सेवा प्रदाताओं को चार साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि व्यवसाय आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों को आसान अस्थायी प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इसने अंतर–कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों के लिए ऊपरी–सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की मोदी सरकार की पहल प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा है। ओमान के साथ समझौता याद दिलाता है कि व्यापारय विकास, रोजगार सृजन और साझा समृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक विभाजित और संरक्षणवादी दुनिया में, पीएम मोदी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि एक नया, आत्मविश्वासी भारत पीछे नहीं हटेगा। यह साझेदारियों, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ेगा।

शादी का झांसा देकर युवती का शोषण करने का आरोप, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,12 जून। यूपी के जौनपुर स्थित गौराबादशाहपुर थाना अंतर्गत शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इनकार करने के आरोप में गौराबादशाहपुर पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ युवती की शिकायत पर पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार मड़ियाहूं क्षेत्र के तदीपुर गांव निवासी एक युवती ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सखैला गांव निवासी विशाल पुत्र सुरेश ने शादी का वादा कर करीब चार वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। युवती का आरोप है कि जब उसने विवाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने विशाल समेत अन्य नामजद लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत शुक्रवार सुबह थानाध्यक्ष गंगासागर मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मेडिकल स्टोर मैरादखान के पास से वांछित अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष गंगा सागर मिश्र ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकार संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।

कौली हत्याकांड 48 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार, पूर्व गृह राज्यमंत्री के आश्वासन पर माने परिजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में बक्शा थाना क्षेत्र के कौली गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई खूनी झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों का विरोध 48 घंटे तक जारी रहा। पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह के हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई के आश्वासन के बाद शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। विदित हो कि 10 जून की रात भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसमें अजय सिंह की मौत हो गई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा, लेकिन परिजनों ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए गुरुवार शाम सदर सीओ देवेश कुमार सिंह, एसडीएम योगिता सिंह, तहसीलदार आशीष सिंह तथा अन्य राजस्व अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया और विवादित भूमि की पैमाइश कराकर सीमांकन भी कराया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। देर रात पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर प्रशासन से कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही घायलों के उपचार और मृतक के बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने की घोषणा की। शुक्रवार सुबह पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह और भाजपा नेता सतीश सिंह कौली गांव पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर प्रशासन की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उनके समझाने–बुझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। गांव में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई है। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, जबकि पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

रोजगार मेले में कैम्पस सलेक्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शासन व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिला सेवायोजन कार्यालय एवं राजकीय आई0टी0आई0 सिद्दीकपुर जौनपुर के संयुक्त तत्वाधान में 12 जून 2026 को प्रातः 10:00 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर परिसर जौनपुर की मोटर वर्कशॉप में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनी मारूति सुजुकी के द्वारा आई0टी0आई0 पास 250 से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कम्पनी द्वारा किया गया शार्टलिस्ट किये जाने के बाद अभ्यर्थियों को अहमदाबाद स्थित मारूति प्लांट हेतु भेजा जाएगा। इस अवसर पर जिला सेवायोजन अधिकारी एवं सहायक सेवायोजन अधिकारी ने जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को बताया गया कि इसी तरह रोजगार मेले के माध्यम से निरंतर सेवायोजन कार्यालय द्वारा 'कैम्पस सलेक्शन कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जायेगा। रोजगार मेले में सेवायोजन एवं आई0टी0आई0 के स्टाफ मौजूद रहें।

मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ, के डॉक्टरों ने एचआईवी पॉजिटिव मरीज का सफलतापूर्वक किया जटिल किडनी ट्रांसप्लांट

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

गोंडा। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, के डॉक्टरों ने गोंडा, उत्तर प्रदेश के 41–वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव मरीज का लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। यह मामला जटिल चिकित्सा परिस्थितियों में भी उन्नत ट्रांसप्लांट देखभाल की संभावनाओं को दिखाता है। जनवरी 2026 में डॉक्टरों ने मरीज को मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, की ट्रांसप्लांट टीम के पास रेफर किया, यहां डॉ. वेंकटेश थम्मिशेट्टी, एसोसिएट डायरेक्टर दृ नेफ्रोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, और डॉ. राहुल यादव व डॉ. आदित्य कुमार शर्मा, डायरेक्टर्स दृ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एवं रोबोटिक यूरो–ऑन्कोलॉजी, ने उनकी पूरी तरह से जांच कर स्थिति समझी और मूल्यांकन किया। जांच के बाद टीम ने उपचार की योजना बनाई, इस योजना में ट्रांसप्लांट के बाद की जरूरतों के मुताबिक उनकी एचआईवी थेरेपी में भी जरूरी बदलाव किए गए। यह मामला जटिल ट्रांसप्लांट स्थितियों को संभालने में बढ़ती चिकित्सा क्षमता को दर्शाता है और उन मरीजों के लिए उपचार के नए रास्ते खोलता है, जिन्हें पहले उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा जाता था।

12 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास और गरीब कल्याण में रचे नए कीर्तिमान – पाशंकर सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सैनिकों और समाजसेवियों को सम्मानित किया। इस दौरान कृपाशंकर सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, जनविश्वास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से करोड़ों लोगों को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है, जबकि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी लगातार बढ़ी है। अभियान के तहत तरहटी मंडल में सेवानिवृत्त सैनिक सुशील पांडे को अंगवस्त्र एवं भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। फत्तूपुर में राज बहादुर सिंह, सत्य नारायण मिश्रा और शिव बहादुर सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं हुलपुर–राजपुर क्षेत्र में इंद्रपाल सिंह एवं सूर्यपाल सिंह तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिवगोविंद साहू और वरिष्ठ समाजसेवी अयोध्या प्रसाद उमरवैश को भी सम्मान प्रदान किया गया। बदलापुर के महाराजगंज क्षेत्र में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास जैसे क्षेत्रों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सतेंद्र सिंह, शिवपूजन पटेल, अरुण पांडे, सुशील मिश्रा, किरण मौर्य, श्याम राज सिंह, राजू केशरी, संजय सिंह, सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दुष्कर्म के मामले में किशोर संरक्षण में लिया गया, बंथरा पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की बंथरा पुलिस ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किशोर को संरक्षण में लिया है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया और विवेचना के दौरान आरोपी किशोर को संरक्षण में लेकर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक बंथरा राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने मामले की जांच की।पुलिस के मुताबिक 9 जून 2026 को पीड़िता की माता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बंथरा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम्ध्6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था।घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा मामले के अनावरण के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने साक्ष्य संकलन और जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 जून को ग्राम लतीफनगर स्थित घर के पास से लगभग 15 वर्षीय किशोर को संरक्षण में लिया।पुलिस का कहना है कि किशोर पर गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप है। मामले में पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।मामले के सफल अनावरण में वरिष्ठ उपनिरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह तथा महिला कांस्टेबल मोनी यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कमिश्नरेट पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है तथा ऐसे मामलों में त्वरित जांच और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

सरोजनी नगर के किसानों को मिला जमीन का अच्छा मुआवजा

लखनऊ, (संवाददाता)। सरोजनीनगर क्षेत्र के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाला मुआवजे में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसानों का कहना है कि यह विधायक राजेश्वर सिंह के प्रयासों के संभव हुआ है। इसको लेकर बुधवार को किसान धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इसमें किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक राजेश्वर सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। सभा में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों ने कहा कि विधायक राजेश्वर सिंह ने उनकी समस्याओं को शासन स्तर पर उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी किसानों का पक्ष रखा। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को यूपीडा से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुआवजा मिला है। अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि सरोजनीनगर किसान सम्मान और विकास का मॉडल बन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की नीतियों, विधायक राजेश्वर सिंह के प्रयासों और प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व की सराहना की।

चारबाग स्टेशन पर सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण चारबाग रेलवे स्टेशन पर हो रही अव्यवस्थाओं पर अंतिम दिन अंकुश लगता नजर आया। बुधवार को स्टेशन को छावनी में बदल दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला। डीआरएम सुनील कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने व्यवस्थाओं की पड़ताल भी की। इसी क्रम में चारबाग रेलवे स्टेशन से दोपहर ढाई से शाम साढ़े छह बजे तक चार परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जबकि लखनऊ जंक्शन से तीन स्पेशल ट्रेनें चलीं। इन ट्रेनों के प्रत्येक कोच में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं, स्टेशन पहुंचने वाले लोगों से पूछ–पूछकर उनके गंतव्य तक जाने वाली ट्रेनों की सूचना दी गई। लगातार अनाउंसमेंट भी होता रहा। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि चारबाग से अयोध्या होकर बनारस के लिए एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन दोपहर ढाई बजे चलाई गई। दूसरी स्पेशल ट्रेन बनारस शाम छह बजे गई। साढ़े छह बजे एक ट्रेन प्रयागराज व झांसी रवाना हुई। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने सीटों पर कब्जा करने, खिड़कियों से घुसने, ट्रेनों के नीचे से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के प्रयास किए, लेकिन जीआरपी व आरपीएफ ने उन्हें रोका। तीन दिवसीय पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा बुधवार को खत्म हो गई। परीक्षा के दौरान बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इस दौरान लखनऊ से 17 शहरों के बीच 124 अतिरिक्त और कुल 500 से ज्यादा बसें चलाई गईं। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ बसों में नहीं नजर आई।

शिविर में वरिष्ठ नागरिकों की सेहत जांची

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में बुधवार को ईपीएस–95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का नौवां स्थापना दिवस गोमतीनगर स्थित निजी अस्पताल में मनाया गया। इस दौरान उपस्थित पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। अस्पताल की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां चिकित्सकों ने बुजुर्गों में होने वाली बीमारियों, उनके बचाव और उपचार की जानकारी दी। आंखों, दांतों, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की निशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम में समिति के केएस तिवारी, राजीव भटनागर, आरएन द्विवेदी, पीके श्रीवास्तव आदि के साथ परिवहन निगम, आवश्यक वस्तु निगम, एचएएल, यूपीट्रॉन, पीसीएफ, आईटीआई और सीड कॉरपोरेशन समेत विभिन्न विभागों के पेंशनर मौजूद रहे।

वेतन में कटौती से भड़के रामकी के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) कंपनी के कर्मचारियों ने बुधवार को वेतन कटौती और नौकरी से निकाले जानी की धमकी के विरोध में गोमती नगर स्थित ट्रांसफर स्टेशन पर जमकर हंगामा– प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि आरोपी सुपरवाइजर राजेश उनके वेतन में दो हजार रुपये की कटौती कर रहा है। कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई तो नौकरी से निकालने की धमकी दी। मामले की जानकारी के बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। इससे करीब तीन घंटे तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां स्टेशन पर ही खड़ी रहीं। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड अभय रंजन ने कहा कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर पासी समाज का प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के महाराजा लाखन पासी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बुधवार को महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति और विभिन्न पासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट नंबर–4 पर नारेबाजी करते हुए नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा। समिति अध्यक्ष डॉ. मोहनलाल रावत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि इतिहासकारों और लखनऊ गजेटियर के अनुसार, लखनऊ की स्थापना महाराजा लाखन पासी ने की थी। सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक रमाशंकर भीम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में लक्ष्मण के किसी नगर की स्थापना का उल्लेख नहीं मिलता। वक्ताओं ने रामभद्राचार्य के बयान (भगवान लक्ष्मण ने बसाया और लाखन पासी ने सजाया) की निंदा करते हुए इसे इतिहास के तथ्यों के विपरीत बताया। राष्ट्रीय पासी मंच के अध्यक्ष विश्रामराज पासी ने कहा कि रामभद्राचार्य को पासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

कुकरैल नदी के कायाकल्प से लेकर नागरिक सुविधाओं तक नगर निगम सक्रिय

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर में स्वच्छता, जल निकासी, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने विभिन्न विकास कार्यों की गति तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बुधवार को कुकरैल नदी, मनोरथा गौशाला, नालों, सीवर व्यवस्था तथा विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम की प्राथमिकता केवल योजनाओं को शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।नगर आयुक्त ने सबसे पहले कुकरैल नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने समता मूलक चौराहे से खुर्रम नगर चौराहे तक नदी के दोनों किनारों का भ्रमण कर सफाई एवं संरक्षण कार्यों की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान नदी में जमा प्लास्टिक, जलकुंभी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुकरैल नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि शहर की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है, जिसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है। नगर आयुक्त ने जोन–3, जोन–4 तथा जोन–7 की टीमों को नदी के दोनों किनारों पर वृहद सफाई अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यदायी संस्था एलएसए के सहयोग से नदी के आसपास सौंदर्यीकरण संबंधी गतिविधियां भी तेज करने को कहा गया। उन्होंने चीफ इंजीनियर मनोज प्रभात को निर्देशित किया कि नदी के भीतर जमा फ्लोटिंग मटेरियल तथा अन्य अपशिष्टों को तत्काल हटाया जाए ताकि जल प्रवाह बाधित न हो और नदी का प्राकृतिक स्वरूप संरक्षित रह सके।कुकरैल नदी के निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त मनोरथा गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सड़क, शेड और बाउंड्री वॉल के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य 20 दिनों के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो।

साइबर सेल की बड़ी सफलता, 15 लाख रुपये कीमत के 65 खोए मोबाइल बरामद कर स्वामियों को लौटाए

लखनऊ, (संवाददाता)। कमिश्नरेट लखनऊ की दक्षिणी जोन साइबर सेल ने आम नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए विभिन्न जनपदों और राज्यों से 65 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई और उन्होंने लखनऊ पुलिस तथा साइबर सेल की कार्यशैली की सराहना की।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन गुमशुदगी से संबंधित मामलों का तकनीकी विश्लेषण कर उन्हें खोजने का कार्य किया जा रहा है।बुधवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनंद के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार के निर्देशन में साइबर सेल, दक्षिणी जोन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। इस अभियान में दक्षिणी जोन के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क की टीमों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों के गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया। जांच के दौरान इन मोबाइल फोन की लोकेशन प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी पाई गई। इसके बाद संबंधित थानों और साइबर टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर मोबाइल फोन को बरामद किया गया।

पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

लखनऊ, (संवाददाता)। बीकेटी क्षेत्र में बुधवार सुबह एक व्यक्ति का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह लगभग 5रू18 बजे ईको कंट्रोल रूम लखनऊ से थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

युवती को बहला–फुसलाकर ले जाने के मामले में बिहार से युवक गिरफ्तार

लखनऊ,(आरएनएस) कमिश्नरेट लखनऊ की चिनहट पुलिस ने युवती को बहला–फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर युवती को सकुशल बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार थाना चिनहट में 6 अप्रैल 2026 को एक महिला द्वारा अपनी पुत्री के अचानक लापता हो जाने की सूचना दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना चिनहट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक प्रियंका राठौर द्वारा की जा रही थी।प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल युवती की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीम ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जनपद में दबिश दी।पुलिस टीम ने 9 जून 2026 को पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित वार्ड नंबर चार, बंगाली टोला, बेरिया कॉलोनी क्षेत्र से युवती को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद नियमानुसार उसके बयान दर्ज किए गए। जांच और बयान के दौरान अजीत वर्मन नामक युवक की भूमिका सामने आई, जिसके बाद उसे मामले में नामजद किया गया।पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए।

'शहादत को नमन, बिस्मिल जन्मस्थली पर रेडक्रॉस सचिव ने श्रद्धांजलि अर्पण कर सेवा ट्रस्ट को भेंट की त्रिपाल'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 129 वीं जयंती के अवसर पर खिरनी बाग स्थित पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जन्मस्थली सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल को नमन किया। डॉ विजय जौहरी ने कहा कि यह पावन जन्मस्थली आज भी भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा का साक्षी है। इसी धरा पर जन्मे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का त्याग, साहस और राष्ट्रप्रेम युवाओं को राष्ट्रसेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। जन्मस्थली भवन की जर्जर स्थिति का अवलोकन करते हुए डॉ जौहरी ने सेवा ट्रस्ट को एक तिरपाल भेंट की, जिससे वर्षा ऋतु में भवन एवं उसके संरक्षण कार्य में कुछ सहायता मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनकी स्मृतियों का संरक्षण हम सबका दायित्वष है।आज हम जिस स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह अमर शहीदों के बलिदान का परिणाम है। ऐसे राष्ट्रनायकों की स्मृतियों का संरक्षण करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। डॉ जौहरी ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जन्मस्थली सेवा ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रस्ट द्वारा शहीद बिस्मिल की स्मृतियों को संजोने, उनकी विरासत को जीवित रखने तथा नई पीढ़ी तक उनके आदर्शों को पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। यह सेवा वास्तव में राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने समाज एवं प्रशासन से भी इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए सहयोग की अपील की तथा अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धापूर्वक नमन किया। डॉ विजय जौहरी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जन्मस्थली सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहीदों की स्मृति में आयोजित ऐसे कार्यक्रम युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, जनसेवा और त्याग की भावना जागृत करते हैं। उउन्होंने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जन्मस्थली सेवा ट्रस्ट एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी संयुक्त रूप से शहीद बिस्मिल की राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की अमर विरासत को संरक्षित एवं प्रसारित करने के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिला प्रबंधन समिति सदस्य अनुज जौहरी भी उपस्थित रहे।

युवा विधि छात्र अत्रि तिवारी की अनूठी पहल, कानून छात्रों के लिए शुरू होगी निःशुल्क इंटर्नशिप

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अयोध्या मंडल के अम्बेडकर नगर जिले मे कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को व्यावहारिक कानूनी ज्ञान एवं शोध कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्ळ ।स्ैम्छैम् प्छक्। द्वारा एक निःशुल्क विधिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व संस्था के संस्थापक एवं युवा विधि छात्र अत्रि तिवारी कर रहे हैं।जानकारी के अनुसार, इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को कानूनी अनुसंधान , केस स्टडी, ड्राफ्टिंग, न्यायिक निर्णयों के विश्लेषण, विधिक लेखन तथा कानूनी जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक अनुभव से भी जोड़ना है।अत्रि तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में विधि छात्र ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई के दौरान पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में यह पहल छात्रों को कानून के क्षेत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने तथा अपने कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि LEGAL SENSE INDIA पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। अब संस्था ने विधि छात्रों के लिए निःशुल्क इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को उनके पेशेवर विकास में सहायता मिल सके।इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इच्छुक विधि छात्र निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।अत्रि तिवारी ने कहा कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को कानून के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें एक सक्षम और जिम्मेदार विधि पेशेवर बनने के लिए प्रेरित करना है।

कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सुरेन्द्र कुमार के पिता के निधन पर सांसद तनुज पुनिया सहित विभिन्न नेताओं संवेदना जताई'

हरदोई। बालामऊ विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव सुरेन्द्र कुमार के पिता श्री राम का निधन हो गया था इस दुःख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सांसद तनुज पुनिया सहित विभिन्न नेताओं ने दुःख संवेदना व्यक्त किया और उन्होंने कहा इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। ईश्वर आपको इस कठिन परिस्थिति को सहने की शक्ति दें।मुझे आपके हालिया नुकसान के बारे में सुनकर बहुत गहरा दुःख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।ष्आपके परिवार के इस अपूरणीय नुकसान पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।परिवार के किसी सदस्य के निधन परष्आपके पिता के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुःख हुआ। वे बहुत नेक इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुःख से उबरने की शक्ति दें।दुःख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। कृपया विश्वास रखें कि हमारी प्रार्थनाएं आपके परिवार के साथ हैं।षमित्रों के लिएष्तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का यह समय बहुत कठिन है। मुझे तुम्हारे पिताध्माता जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुःख पहुँचा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।इस दुखद घड़ी में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको और आपके परिवार को शांति और धैर्य दे।

सैनिक विहार में लो वोल्टेज से परेशान रहे उपभोक्ता

गोरखपुर, (संवाददाता)। सैनिक विहार कॉलोनी में मंगलवार देर रात बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद भी उपभोक्ताओं को रातभर लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ा। स्थिति ऐसी रही कि बल्ब तो जल रहे थे, लेकिन पंखे बेहद धीमी गति से चल रहे थे। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह करीब चार बजे के बाद वोल्टेज सामान्य हुआ, तब जाकर एसी समेत अन्य बिजली के उपकरण चले और लोगों ने राहत की सांस ली। उधर, शाहपुर क्षेत्र के पीएसी फीडर पर दिन में करीब दो घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। इससे लगभग एक हजार उपभोक्ता प्रभावित हुए और गर्मी के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

खजांची–पादरी बाजार मार्ग पर खुले हैं नाले, चलें तो जरा संभलकर

गोरखपुर, (संवाददाता)। खजांची चौराहे से पादरी बाजार जाने वाले मार्ग पर हरसेवकपुर नंबर–दो के राजनगर मोहल्ले के पास अधूरा नाला हादसों को दावत दे रहा है। इस जगह पर करीब 200 मीटर लंबाई में नाले पर स्लैब नहीं लगे हैं। नाला पूरी तरह से खुला है। यहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यहां पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि एक दिन पहले ही इसी नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। हादसे के बाद उस जगह को अस्थायी रूप से घेर दिया गया है। इसी जगह पर गोड़धोईया नाला निर्माण भी चल रहा है। आगे कुछ दूरी पर जाने पर सड़क से सटा यह नाला पूरी तरह खुला पड़ा है। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में लकड़ी, पटरी का रास्ता बनाकर आते–जाते हैं। नाले के किनारे दुकानें भी हैं। एक निजी अस्पताल भी है जहां मरीजों और तीमारदारों का आना–जाना लगा रहता है। ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दुकानदार पप्पू ने बताया कि नाले की गहराई काफी अधिक है और सड़क से इसकी दूरी भी बहुत कम है। रात के समय या बारिश में स्थिति और खतरनाक हो जाती है। दुकानदार जुगनू ने बताया कि सड़क की ऊंचाई नाले से अधिक है। बाइक और साइकिल सवारों को हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए चलना और भी जोखिम भरा है। नाला तो बन गया लेकिन स्लैब न लगने और सुरक्षा इंतजाम न होने से लोगों की जान को खतरा है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को बैरिकेडिंग कर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। जहां भी नाले खुले हैं, उन्हें तत्काल ढका जाएगा। यदि लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या।रविवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर व अन्य पुलिस कर्मियों ने जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर महिला कांस्टेबल ,प्रेया सिंह सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

'जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे हुआ रात्रि चौपाल का आयोजन'

'ब्यूरोरिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' केन्द्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के गौरवपूर्ण 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक संचालित होने वाले वृहद अभियान घ्के अन्तर्गत विगत दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे विकास खण्ड बावन में रात्रि चौपाल आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने चौपाल में लगे विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया, तथा कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी तथा बच्चों का अन्नप्राशन कराया। जिलाधिकारी ने चौपाल में लोगों से संवाद कर उन्हें शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। घ्रात्रि चौपाल के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सभी पात्रों को लाभान्वित किया जाय तथा शिकायतों एवं समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध तथा प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कार्यक्रमों एवं योजनाओं से भी आम जनमानस को अवगत कराया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में शासन की उपलब्धियों के विषय में चर्चा की गई। घ्रात्रि चौपाल के दौरान ब्लॉक प्रमुख बावन प्रतिनिधि धर्मेन्द्र सिंह, पीडी ए के मौर्या, डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय, डीएसटीओ राम प्रकाश, प्रधान व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

10 पेड़ गिरे, 26 बिजली के खंभे टूटे- दो रात लोगों ने अंधेरे में गुजारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। वनटांगिया क्षेत्र के लोगों को बीते सोमवार की दोपहर से भीषण कटौती का सामना करना पड़ा। लगातार दो रात बिजली न रहने से पूरा इलाका अंधेरे और उमस भरी गर्मी की चपेट में रहा। भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल होने से स्थानीय लोगों के सामने पेयजल और जलापूर्ति का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल संबंधित बिजली निगम के अधिकारियों को दी गई थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती और लंबे समय तक आपूर्ति बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे ग्रामीणों को दो रातें और तीन दिन नरकीय स्थिति में काटने को विवश होना पड़ा। बुधवार की शाम करीब 06रू30 बजे बिजली आपूर्ति दोबारा चालू हो सकी। पूरे 50 घंटे से अधिक समय के बाद बिजली आने पर स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। रजही क्षेत्र स्थित वनटांगिया बस्ती की हरिजन बस्ती, सोखा टोला और रामसरिया टोला के 200 परिवारों के 1,000 से अधिक लोग सोमवार दोपहर आई आंधी के बाद से ही अंधेरे में रहने को विवश थे। आंधी के कारण जंगल में बिजली के 26 पोल टूट गए थे, इससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद बिजली निगम ने बुधवार से पोल ठीक करने और तार खींचने का काम शुरू किया। इस दौरान पूरे दिन लोग बिजली न होने से परेशान रहे। क्षेत्र के रामदयाल निषाद और राजकुमार ने बताया कि सोमवार को आई आंधी के बाद से ही यहां बिजली आपूर्ति ठप थी, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में नईयापार के जेई सुभाष चंद्र मौर्य ने बताया कि आंधी के कारण 10 बड़े पेड़ गिर गए थे।

खड़े टैंकर से कार की भीषण टक्कर, महिला की मौत

वाराणसी, (संवाददाता)। सोनभद्र जिले के बभनी– अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर विष्णु प्रिया ढाबा पोखरा के पास गुरुवार सुबह खड़े टैंकर में कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पति–बेटी सहित परिवार के पांच लोग घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बलिया जिले के सिकंदरपुर निवासी एक परिवार कार से रेणुकूट होते हुए रायपुर (छत्तीसगढ़) जा रहा था। सुबह बभनी–अंबिकापुर मार्ग पर विष्णु प्रिया ढाबा पोखरा के पास सड़क किनारे खड़े टैंकर में कार पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों और राहगीरों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने रूचि सिंह (33) पत्नी पवन सिंह निवासी सिकंदरपुर, बलिया को मृत घोषित कर दिया। हादसे में यतेंद्र सिंह (70) पुत्र धर्मदेव सिंह, मालती सिंह (65) पत्नी यतेंद्र सिंह, पवन सिंह (35) पुत्र यतेंद्र सिंह, पंकज सिंह (32) पुत्र यतेंद्र सिंह तथा रिमझिम (4) पुत्री पवन सिंह घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने यतेंद्र सिंह और पवन सिंह की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी भेज दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और चालक को झपकी आने के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है।

मानसून की उलटी गिनती शुरू सड़कों का काम आधा अधूरा

भदोही, (संवाददाता)। मानसून आने में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर से लेकर गांव तक की कई सड़कें जर्जर हालत में हैं। 40 सड़कों पर निर्माण काम आधा अधूरा है। निर्माणाधीन सड़कों को बारिश से पहले पूरा कराना मुश्किल है। करीब 150 करोड़ रुपये से बनने वाली इन सड़कों का कार्य अधूरा रहने से मानसून के दौरान लोगों की दुश्वारियां बढ़ेंगी। वहीं, बारिश के कारण सड़क निर्माण कार्य भी प्रभावित होगा, जिससे बड़ी आबादी को परेशानी उठानी पड़ेगी। जिले की 546 ग्राम पंचायतों और सात नगर निकायों में करीब 2500 किलोमीटर सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति समेत विभिन्न एजेंसियां सड़कों की देखरेख करती हैं। सभी निर्माण कार्यों का नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग है। मुख्य सड़कों पर हर वर्ष ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें खराब बनी रहती हैं। शासन ने 15 जून से पहले सड़कों के गड्ढे भरने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक ऐसी सड़कों की सूची ही तैयार नहीं हो सकी है। जिन सड़कों पर कार्य चल रहा है, उनका काम भी समय से पूरा होता नहीं दिख रहा है। तारकोल की कमी और कागजी प्रक्रिया के कारण प्रभावित करीब 50 सड़कें मानसून में लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। सबसे अधिक ज्ञानपुर विधानसभा की सड़कें रू जिले में इन दिनों जिन सड़कों के नवीनीकरण का काम चल रहा है। उसमें अधिक सड़कें ज्ञानपुर विधानसभा की हैं। करीब 40 निर्माणाधीन सड़कों में 20 ज्ञानपुर विधानसभा और 12 से 14 औराई विधानसभा और करीब छह से सात सड़कें भदोही विधानसभा की हैं। इन सड़कों का काम मानसून सीजन से पहले पूरा होना मुश्किल दिख रहा है।

बिजली के खंभे में लगी आग, बाक्स व तार जले

भदोही, (संवाददाता)। नगर के नोनियानी गली में बुधवार सुबह एक बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। आग ने खंभे से लगे केबल बॉक्स व तारों को भी अपने चपेट में ले लिया। मोहल्ले के निवासी मजहरउल्ला गुड्डू ने बताया कि अचानक आग लगने से पोल पर लगे बिजली के तार धू–धू कर जलने लगे। जिससे मोहल्ले की आपूर्ति बाधित हो गई। बताया कि तेज चिंगारियों और धमाकेदार आवाजों के बीच पोल, तार व केबल बॉक्स जलकर राख हो गए। लोगों ने बिजली निगम के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद तत्काल क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। बताया कि संयोग ही था कि आग की लपटें आसपास के मकानों तक नहीं पहुंचीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पास में एक साइकिल स्टोर का गोदाम भी है। आग से पूरे मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। जेई दीपक पांडेय ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग लगी होगी। क्षतिग्रस्त तारों और उपकरणों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। गोपीगंज बाजार में बीती रात तेज आंधी तूफान और बरसात के बाद सदर मोहल खड़हट्टी मोहाल सहित मिर्जापुर रोड बड़े शिव मंदिर के आसपास आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति का एक फेस पूरी रात प्रभावित रही।

स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होगा ज्ञानपुर, आठ करोड़ से होंगे काम

भदोही, (संवाददाता)। नगर के विभिन्न वार्डों में अब स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकास कार्य कराए जाएंगे। शासन स्तर से नगर पंचायत का चयन नवयुग पालिका योजना के तहत किया गया है। योजना के तहत नगर के 11 वार्डों में आठ करोड़ रुपये से नाली, इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था के अलावा नए कार्यालय का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेन्स, ई–सेवाओं और तकनीकी समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों वाले नगरीय निकायों का चयन एक महीने पहले नवयुग पालिका योजना में किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य निकाय में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। योजना में सड़कों, जल निकासी, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना है। जिला मुख्यालयों को विकसित करने से विभिन्न विभाग के बीच विकास की असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत नगर सभी तिराहे, चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा। हाईमास्ट लाइट, बेंच, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। नगर में कुल 11 वार्ड है, यहां करीब 25 से 30 हजार की आबादी निवास करती है। यह मुख्यालय की नगर पंचायत है। आगामी समय में इसे पालिका बनाने की योजना चल रही है। नगर पंचायत के विभिन्न वार्ड में हर साल लाखों रुपये खर्च करके अलग–अलग मद से नाली, इंटरलॉकिंग, सड़क सहित अन्य कार्य कराए जाते हैं, लेकिन जल निकासी व्यवस्था का अस्थाई समाधान नहीं निकल पाता है। अब इन समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से हो सकेगा। योजना के तहत होने वाले कार्यों की निगरानी सीधे लखनऊ से की जाएगी।

पहली पाली में 674 व दूसरी में 627 रहे अनुपस्थित

भदोही, (संवाददाता)। जिले में बनाए गए छह केंद्रों पर बुधवार को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। नकल रोकने को लेकर जहां गेट पर जांच कर अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश दिया गया। जिलाधिकारी शैलेष कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर सहित अन्य केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिले में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, विभूति नारायण राजकीय इंटर कालेज, ज्ञानपुर, जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज ज्ञानपुर, गुलाबधर मिश्र इंटर कालेज, गोपीगंज, एमए समद इंटर कालेज भदोही एवं श्रीइंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कालेज भदोही को केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।